MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Now I will put the clauses to the vote of the House. The question is :

"That clauses 2, 3 and 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, *and* 1 *the Schedule, the Enacting, Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI MORARJI DESAI : I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

19.11 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

NEGOTIATIONS WITH CHINA

MR. SPEAKER : Now we shall take up the Half-an-Hour discussion, given notice of by Shri Prakash Vir Shastri.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Sir, we may take it up tomorrow.

MR. SPEAKER : I do not know. May be, some other important thing is fixed for tomorrow. Then, it will be pushed out and it will never get any time. It is an important matter. Also, it is only 7.15 p.m. Let us hear Shri Shastri. Even if we postpone it to tomorrow, then also hon. Members will go away. So, we will take it up now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चीन के साथ बात चीत करने के सम्बन्ध में संवाददाता सम्मेलन में जो वक्तव्य दिया था, मेरी आधे घण्टे की चर्चा मुख्य रूप से उसी को आधार मान कर है। आज जब मैं यह चर्चा इस सदन में कर रहा हूं, आप को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही नाथूला में चीनियों की ओर से कुछ उत्तेजनात्मक और भड़काने वाली कार्रवाइयां की गई हैं। अभी पीकिंग में भी कुछ दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन समाप्त हुआ है। उस में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की है कि सह-अस्तित्व की जो हमारी पुरानी नीति है उस से हम हट रहे हैं और प्रतिक्रियावादियों का दमन करने के लिये जो भी साधन प्रयोग में आ सकते हैं उन का प्रयोग किया जाना चाहिये; चाहे वह रूस में हों चाहे कहीं और हों।

आज जब मैं इस चर्चा को प्रारम्भ कर रहा हूं तब, अध्यक्ष महोदय, शायद आप को यह जान कर आश्चर्य न हो कि पीकिंग की साम्यवादी पार्टी के सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में जो एक रिर्पोट दी गई है उस में भारत के सम्बन्ध में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वहां पर सशस्त्र क्रांति धीरे-धीरे अपने पैर बढ़ाने लगी है इस से भी भंयकर बात यह है वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह जो यहां बैठे हैं उन्हें मालूम होगा—कि अभी 8 अप्रैल को रूस और चीन सीमा सम्बन्धी विवाद को ले कर यहां उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। उस के सम्बन्ध में चीन के लोगों ने अपनी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है। उस के शब्द इतने घृणित और इतने अपमानित करने वाले हैं जिस की सीमा नहीं है। अगर मैं उन के शब्दों को हिन्दी में यहां कहूं तो यह कहा जा सकता है कि :

"तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जायेगी, चाहे तुम सामने आओ अथवा अपने हिमायती रूस को साथ ले कर आओ।"

ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधान मन्त्री की ओर से इस प्रकार का वक्तव्य आना कि चीन के साथ हम बात चीत करने के लिये तैयार हैं, कहां तक देश के स्वाभिमान के अनुरूप है ?

एक बात जो यहां. मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि प्रधान मन्त्री ने कहा कि :

"चीन ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसे हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन हमें इस बारे में रुके नहीं रहना चाहिये और किसी न किसी तरह समस्या को हल करने का मार्ग निकालना चाहिये । मेरा विचार है कि समस्या जितनी कठिन हो उस को हल करने का मार्ग निकल ही सकता है ।"

प्रधान मंत्री ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या भारत अब भी इस बात पर दृढ़ है कि जब तक चीन कोलम्बो प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेता तब तक चीन से कोई बातचीत नहीं की जा सकती । यह तो हमारे प्रधान मन्त्री का वक्तव्य है । लेकिन श्री दिनेश सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस से कुछ अलग ही बात कही है । उन्होंने कहा है कि :

"सरकार ने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि वह किसी ऐसे आधार पर, भारत और चीन के बीच के सभी मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिये इच्छुक है, जो भारत की प्रादेशिक अखण्डता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान के अनुकूल हो । 1 जनवरी, 1969 को जो पत्रकार सम्मेलन हुआ था, उस में प्रधान मन्त्री ने फिर से यह स्थिति दोहराई थी ।"

जो कुछ मैंने पढ़ कर सुनाया और जो कुछ विदेश मंत्रालयके उत्तर में है उस की भाषा में जमीन आसमान का अन्तर है । प्रधान मन्त्री ने प्रादेशिक अखण्डता के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा जब एक पत्रकार ने उन से पूछा कि क्या चीन भारत का सब से बड़ा शत्रु है, क्या आप इस बात को स्वीकार करती हैं ? तब प्रधान मंत्री ने इस बात को मानने से भी इन्कार कर दिया और कहा कि चीन को भारत का सब से बड़ा शत्रु कैसे माना जा सकता है ? उन का यह वक्तव्य इतना चिन्ता का विषय है जो इस को केवल यहां के पत्रों ने ही नहीं, प्रधान मन्त्री के अपने परिवार का पत्र जो "नेशनल हेराल्ड" है उस ने भी प्रमुख न्यूज के रूप में इसे दिया है । और भी जितने पत्र हैं करीब करीब उन सब ने प्रमुख समाचार के रूप में इस को दिया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे कर और प्रधान मंत्री के वक्तव्य को छिपाने का यत्न करना कहां तक समझदारी है ।

पीछे चीन का हमला भारत पर हुआ । उसके बाद इसी सदन में 25 जनवरी, 1963 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया । उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जब तक चीन आठ सितम्बर, 1962 की स्थिति में लौट कर चला नहीं जाता तब तक चीन के साथ कोई प्रारम्भिक बातचीत करने का भी सवाल पैदा नहीं होता । उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से एक वक्तव्य राष्ट्र के नाम प्रसारित किया और उस वक्तव्य में उन्होंने यह कहा कि हम इस बार दीवाली का त्यौहार इस वास्ते खुशी के साथ नहीं मना रहे हैं क्यों कि हमारी बहुत सी धरती पर चीन अधिकार किये बैठा है । हमारी लगभग साढ़े चौदह हजार मील की धरती पर चीन ने अधिकार कर लिया है । दीवाली हम खुशी के साथ उस दिन मनायेंगे जिस दिन हम अपनी धरती को चीन से वापिस ले लेंगे । यह सन्देश उन्होंने रेडियो से राष्ट्र के नाम प्रसारित किया था ।

इसके बाद इस सदन ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया । प्रस्ताव बहुत बड़ा है । मैं पुरा प्रस्ताव न पढ़ कर उसका अन्तिम पैरा ही पढ़ कर सुनाता हूं जिस में सारे सदन ने एक मत से चौदह नवम्बर, 1962 को यह संकल्प किया था :

यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का आशा और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मैं पूछना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू का जो वक्तव्य है, आज की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उससे हट गई हैं क्या ? संसद् ने जो प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था, उस प्रस्ताव से विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री हट गये हैं क्या ?

उसके बाद दूसरे प्रधान मन्त्री आये, श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने 24 दिसम्बर, 1964 को इसी सदन में एक वक्तव्य देते हुए कहा कि भारत सरकार पारस्परिक चर्चा द्वारा मामले तय तो करना चाहती है परन्तु ऐसी चर्चायें देश के गौरव और सम्मान को किंचित मात्र कोई आघात पहुंचाये बिना ही की जा सकती हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्टैण्ड यह था । इस लिये जब श्री जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड भी यही था कि जब तक चीन हमारी धरती को खाली न कर दे, तथा संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बदले कोई दूसरा प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया है, और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा उसको सामने रखते हुए, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को क्या अधिकार था कि वह पत्रकार सम्मेलन में इस प्रकार का वक्तव्य देतीं कि चीन के साथ बातचीत की जा सकती है। ऐसा करके उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन संसद को दिया था, उसकी भी उपेक्षा की, संसद् में पारित प्रस्ताव की भी उपेक्षा की और श्री लाल बहादुर शास्त्री के आश्वासन की भी उपेक्षा की । साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधियों ने जो अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, उस की भी उपेक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की।

असली बात और है। जिस समय चीन ने हमारी धरती पर हमला किया, तब श्री कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। वह बार-बार कहते रहे कि चीन भारत पर हमला करने वाला नहीं है। लेकिन जब चीन ने हिन्दुस्तान की धरती पर हमला कर दिया उस दिन से फिर कुछ रुक कर उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि चीन के साथ हमें बातचीत करनी चाहिये। चीन के साथ बातचीत का दर्वाजा हमें बन्द नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि श्री कृष्ण मेनन के उस वक्तव्य से प्रभावित हो कर ही हमारी प्रधान मन्त्री ने पत्रकार सम्मेलन में इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति क्या यह सरकार तय करती है या हमारी विदेश नीति आज भी श्री कृष्ण मेनन से प्रभावित है ? प्रधान मन्त्री जैसे उच्च पद पर बैठी हुई श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

राजेन्द्र बाबू जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनके सामने ही हमारी धरती पर हमला हुआ। राजेन्द्र बाबू ने पटना के गांधी मैदान में जो कहा वह मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इसकी प्रायश्चित एक ही है। उस समय जब तिब्बत को चीनी राक्षस हड़प कर रहा था हम अपनी जबान पर ताला लगाये बैठे रहे। एक ही प्रायश्चित अब इस सारी भूल का हो सकता है कि हम अपनी धरती को भी चीनी राक्षस से मुक्त करायें और तिब्बत को भी चीन से मुक्त करायें। जब हम ऐसा कर लेंगे तभी हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रधान मन्त्री ने लगता है राजेन्द्र बाबू के वक्तव्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया । पहले दो प्रधान मंत्रियों ने जो कहा था उस पर भी ध्यान नहीं दिया । और ऐसी हलकी बात पत्रकार सम्मेलन में कह कर देश के स्वाभिमान और त्याग पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। यह स्थिति तब है जब चीन ने अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने बार बार वार्ता का प्रस्ताव किया है लेकिन चीन की ओर से अभी तक कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। चीन एटम बम बना रहा है हाइड्रोजन बम बना रहा

है, पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लड़ाई के हथियार दे रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना आधिपत्य जमाने के लिये तरह तरह के प्रयास कर रहा है। फिर समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार ने कौन सी विशेषता इस प्रकार की देखी कि जो उसके प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार की बात कह दी कि हम चीन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। यह बिना किसी प्रकार से पुराने आश्वासनों को ध्यान में रखे हुए कह दी।

सब से बड़ी बात तो यह है कि श्री जवाहर-लाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी इसी सदन में 25 जनवरी, 1963 को दिया था। मैं उन के शब्दों को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"शासन का यह कर्त्तव्य है कि वह समय-समय पर संसद् को महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सूचित करता रहे। जब संसद् नीति निश्चित कर दे, तभी शासन उस पर कार्यवाही करे।"

श्री जवाहर लाल नेहरू का यह वक्तव्य है कि जब तक संसद् किसी नीति पर अपनी मुहर नहीं लगा देता है, तब तक सरकार के किसी भी मिनिस्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार की महत्वपूर्ण नीति में परि-वर्तन के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे दे। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू के इस दूसरे वक्तव्य की भी उपेक्षा क्यों की गई।

यह सरकार आज जनरल मरचेंट की दुकान बनी हुई है। जब कोई सुरक्षा विषयक चर्चा होती है तो डिफ़ेंस मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह, जिस भाषा में बोलते हैं उससे लगता है कि वह भाषा देश की आत्मा के अनुकूल है, वह देश के गौरव की रक्षा और देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन प्रधान मन्त्री जिस भाषा का प्रयोग करतीं हैं, उससे लगता है कि वह देश के स्वाभिमान की उपेक्षा करके और उसके त्याग तथा तपस्या पर धूल डाल कर उन को समाप्त करने की भाषा बोल रहीं हैं।

मैं चाहता हूं कि आज वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह, स्पष्ट रूप से देश को बताएं कि क्या सरकार अपनी उस पुरानी नीति पर दृढ़ है, जो श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सामने रखी थी, जिस का प्रतिपादन इस संसद् द्वारा पारित प्रस्ताव में किया गया था और जो नीति श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी थी? अथवा सरकार ने उस नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर लिया है? अगर कोई परिवर्तन किया है तो उस के सम्बन्ध में संसद् को विश्वास में क्यों नहीं लिया? सरकार से हटने के बाद भी श्री कृष्ण मेनन चीन के सम्बन्ध में जो वक्तव्य देते रहे उन से प्रभावित होकर हमारी प्रधान मन्त्री का इस प्रकार के वक्तव्य देना देश के स्वाभिमान के कहां तक अनुकूल है?

मुझे विश्वास है कि वैदेशिक कार्य मंत्री इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वक्तव्य देंगे, जिस से देश में फिर से इस प्रकार की ग़लतफ़हमियां पैदा न हों।

MR. SPEAKER : There are four other names. They may kindly take one or two minutes each. Shri Ranga.

SHRI RANGA (Srikakulam) : We have no objection to Government having talks with anybody. When they are willing to have talks with Pakistan, why should they not have talks with China ? But we must be clear about the stand which we took on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the 14th November, as my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri reminded the Government. On what basis could we having talks, if at all, they condescend to have talks. It is unfortunate that we should have said it in such a unilateral manner.

We would like to know whether Government would respect the wishes of the House and also of the people in the country that Tibet's sovereignty should come to be respected and it should be resorted through our efforts and also by our good offices through the efforts of the United Nations.

[Shri Ranga]

Secondly, we would like to know whether we would insist upon that the 14,000 and odd sq. miles of land which have been unconstitutionally and immorally occupied by China should be disgorged by them and should be given up by them. If we are not going to keep these two demands in our mind, in our negotiations, it will be worthless to have any kind of talks with them.

I wish to sound this warning on behalf of our party and other people in the country also that whatever may be present policy and tactics of the Government, whatever be the kind of agreements they may find themselves forced to reach some day or the other, we would not hold our responsibility for them nor we would recommend to Government to accept them unless Tibet's sovereignty comes to be recognised by China, and we protect it, and the land that has been taken over by China is regained by us and, as they put it, our integrity and sovereignty come to be respected by China in a decent civilised manner.

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : अध्यक्ष जी, शास्त्री जी की भावनाओं को देखते हुए यह ठीक है कि राष्ट्रीय भावना उन में ओत-प्रोत है और वह हमारे पूजनीय भी हैं मगर में इस परिस्थिति में, इस माहौल में अपने विदेश मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि पहली जनवरी, 1969 को जब प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया उस वक्तव्य के पीछे क्या यह परिस्थिति थी कि रूस जो अब तक हमारे साथ मित्रतापूर्ण और सौहार्द-पूर्ण सम्बन्ध रखता था, उसने पाकिस्तान को जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है आर्म्स ऐंड ऐम्युनिशंस की मदद दे करके हमारे अन्दर उस मित्रता के प्रति सन्देह पैदा कर दिया, क्या इस माहौल में उन्होंने यह वक्तव्य दिया जिससे कि चीन जो हमारा बहुत जबर्दस्त दुश्मन रहा है उस के साथ कुछ संबंध सुधरें और जो कि रूस अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति में एक शिफ्ट लाया है उस की पृष्ठभूमि में हमारा कुछ संबंध इन के साथ बने ? क्या इस वक्तव्य के पीछे यह भावना थी ?

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, यहां पंडित जवाहर लाल नेहरू को कोट किया गया है। उन्होंने यह कहा कि जब तक हमारी भूमि आजाद नहीं हो जाती तब तक हम कोई संबंध चीन के साथ नहीं करेंगे लेकिन मैंने यह सुना है 1962 के हमले के बाद चाऊ एन लाई हिन्दुस्तान आए थे। उतना स्वागत नहीं मिला था लेकिन फिर भी स्वागत हुआ था, बातें हुई थीं। तो कामनसैंस और व्यावहारिकता का तकाजा है कि कम से कम, दुश्मन से बातचीत जारी रहनी चाहिए यदि आप खुले आम दुश्मन से लड़ने के लिये तैयार नहीं है तो। प्रधान मंत्री जी ने जो कहा कि बातचीत के लिए हिन्दुस्तान तैयार है, मैं यह नहीं समझता हूं कि वह दुरुस्त उन्होंने नहीं कहा। इस सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान कम्युनिस्ट चीन को युनाइटेड नेशंस में मान्यता मिल जाय इस के लिए बराबर बोलता रहा है लेकिन हमले के बाद से कितनी दफा हिन्दुस्तान ने यह बात उठाई है और क्या चीन की मान्यता दिलाने के लिए हिन्दुस्तान अभी भी तैयार है ?

दूसरा सवाल है कि आप के पोलिटिकल रिलेशंस नहीं होते हैं तो कम से कम ट्रेड और एकोनामिक रिलेशंस की सम्भावन तो हो सकती है, तो क्या उस ओर सरकार सोच रही है कि हमारे व्यापारिक रिश्ते चीन के साथ हों और उस पर बातचीत चले ?

तीसरा सवाल है हकीकत में हमारी कुल कितनी भूमि चीन के मातहत है ? और, चौथा सवाल है कि यह जो अभी हमले हुए, वार स्टरिंग्स हुए नाथूला के पास, इससे जो बातचीत का सिलसिला पहले से रहा है क्या उस पर आघात होने जा रहा है ?

SHRI TULSHIDAS JADHAV (Baramati) *rose*—

MR. SPEAKER : This is half-an-hour discussion. Your name is not there.

SHRI TULSHIDAS JADHAV : Four members are allowed.

MR. SPEAKER : Lots are drawn. Your name was not there. I cannot help it. It is not in my hands. The name of Mr. B. S. Sharma is there, but he is not present.

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शास्त्री जी ने, यह सवाल उठाया कि सरकार ने और हमारे पहले के आदरणीय प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य इस सदन में दिया है और जो विश्वास उससे देश में और सदन में पैदा हुआ है, क्या सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जो कि उस के विपरीत हो ? मैं चाहता हूं कि बिना किसी बात में कोई शक पैदा किये मैं इस को सबसे पहले साफ कर दूं कि सरकार के जो कोई भी यहां पर वक्तव्य सदन में हुए हैं और जो कोई भी सरकार ने अंडरटेकिंग सदन को दी है हम उसके बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं न जा सकते हैं। और आज इस बात को कहना कि सरकार जो कोई भी विश्वास उस ने सदन को दिया हो, उस के बाहर जा रही है , मैं समझता हूं कि यह सरकार के साथ कोई इंसाफ नहीं है । माननीय सदस्य इस में विश्वास रखें कि जो कोई भी हमने आश्वासन इस सदन को दिया है उस आश्वासन से हम बंधे हुए हैं और बिना उन आश्वासनों के सदन से बदले हुए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस से कोई देश के हित की हानि हो ।

अब इन्होंने कुछ खास बातें रखीं हैं और मुझे दुख है कि इन बातों के बारे में देश के कुछ विशेष अखबार बीच बीच में शक पैदा करते रहे हैं, मैं क्या कहूं अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत से अखबार हैं, बहुत से लोग उनको लिखते हैं, जिम्मेदारी से लिखते है, ऐसा मानता हूं, मैं कम से कम कोशिश करते हैं, फिर भी बहुत सी बातें ऐसी छपती, जिनको कि देख कर बहुत ताज्जुब होता है कि वास्तव में वह लोग क्या कहना चाहते हैं। उनके पास जनता को अपने विचार देने के साधन हैं, वे उसका इस्तेमाल करते हैं । हम तो उन से यही आशा करेंगे कि उनकी जो जिमेदारी है जनता को सही खबर देने की, वे उस को निभायेंगे । हमें तो, अध्यक्ष महोदय, यही मौका मिलता है, जब कि आप अवसर प्रदान करते हैं या बाहर भी कहने का मौका मिलता है, जब कि हम अपनी बात को साफ कर सकते हैं ।

अभी शास्त्री जी ने कहा और शायद अखबारों में भी छपा हो कि प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हम चीन से बात करेंगे । कुछ ऐसा इम्प्रेशन भी पैदा किया है कि पुरानी बातों को भूलकर ऐसा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी उस दिन भी प्रधान मंत्री जी ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में सवाल-जवाब में ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे जरासी भी कोई गलतफहमी पैदा हो सके । जब प्रधान मंत्री से चीन के बारे में पूछा गया, उन्होंने साफ कहा—मैं उसी में से कोट कर रहा हूं—

A solution can only be found keeping the national interests, national honour and interest in mind.

बिल्कुल साफ बात कही गई है, शक की कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि देश के हित की बात ही सब से ऊपर हमारे दिमाग में रहेगी ।...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा स्पष्ट कहना यह था कि जैसा जवाहरलाल जी ने कहा था कि जब तक 8 सितम्बर की पोजीशन नहीं आ जाती, चीन हमारी धरती खाली नहीं कर देता, तब तक हम कोई प्राथमिक बात भी नहीं करेंगे ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय शास्त्री जी ने जो कहा है मुझे याद है, मैं कोशिश करूंगा कि सब बातों का जवाब दूं, लेकिन मुझे एक एक कर के कहने दें तो आसान होगा ।

यह सवाल इस सदन में कई मतबा आया है और मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि जब भी चीन के साथ हमारी बातचीत होगी, हम अपने देश की प्रभुसत्ता, अखण्डता और अपने देश के

[श्री दिनेश सिंह]
स्वाभिमान को कभी भी नहीं छोड़ेंगें—यह बात साफ तौर से कही गई है।

अब सवाल यह उठता है कि कोलम्बो प्रपोजल्ज के अनुसार उनसे बात की जाय या न की जाय या चीन जब तक हमारी भूमि का एक एक इंच छोड़ न दे, तब तक उन से बात करें या न करें—माननीय शास्त्री जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, शुरू से ही वे इस सदन में इस विषय पर चर्चा करते आये हैं, काफ़ी दिलचस्पी उन्होंने इस विषय में ली है—आपको याद होगा कि जब कोलम्बो प्रपोजल्ज हमारे सामने आये थे—उसमें यह था कि जहां तक वेस्टर्न सैक्टर (पश्चिम सैक्टर) की बात थी, चीन आज जहां है. वहां से 20 किलोमीटर पीछे हट कर बात करे, लेकिन 20 किलोमीटर हटने पर भी वह भारत की भूमि में रह जाता है। ये जो बातें हैं इनको आप पिछले सन्दर्भ से देखें तो बिलकुल स्पष्ट हो जाती हैं। हमारी जो भावना है......

SHRI RANGA : That was not accepted by Parliament.

श्री दिनेश सिंह : मैं इसी लिये अर्ज कर रहा हूं कि जिस कोलम्बो प्रपोजल की चर्चा शास्त्री जी ने की है, उसके आधार पर भी यह बात रह जाती है। इन सब बातों को हमको और आप को देखना है।

कोलम्बो प्रपोजल्ज की यहां पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। माननीय रंगा जी भी बहुत पुराने सदस्य हैं, उन्होंने भी उस चर्चा को सुना है, इसमें कोई बात छिपी नहीं है। जो कुछ भी समस्या है, कठिनाई है, पेच है, सब पर सदन के सामने विस्तारपूर्वक बहस हो चुकी है। मैं तो आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन की इच्छा के विरुद्ध कोई भी ऐसी चीज छिपा कर करने वाली नहीं है, जिसमें हमारे देश की प्रभूसत्ता अखण्डता या देश के सम्मान की हानि हो।

एक बात जरूर उठती है—जब प्रधान मंत्री जी से प्रेस कान्फ्रेंस में बार बार पूछा गया कि आप किस आधार पर बात करेंगी—दूसरा क्या आल्टरनेटिव है? तब भी उन्होंने साफ साफ कहा—

That was not a correct assumption. The point is that we want to solve something. There is no point in saying very categorical views. Our views are known.

इसका मतलब यह नहीं है कि व्यूज़ बदल गये हैं। हमारे व्यूज मालूम हैं लेकिन उनको हर समय उसी तरह से दोहराने में कोई खास फायदा नहीं होता है। उन्होंने आगे भी कहा है :

> "Our views are known to those people and we shall certainly not let them get any wrong impression..."

तो हर तरह से प्रधान मन्त्री ने, उनका जो अपना स्टैंड था, उसको साफ किया और कहा कि हम चीन से मैत्री चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत और चीन के जो निवासी हैं उनके बीच में मैत्री हो लेकिन वह मैत्री हमारे देश के अहित से नहीं हो सकती है। हमारे देश के हित में और चीन के हित में यह है कि हम दोनों मिलकर रहें, एक दूसरे के बीच में मैत्रीपूर्ण भाव रहे लेकिन वह भाव तभी हो सकता है जब चीन भी हमारे देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को माने। मैंने जब यहां पर अपने मंत्रालय के बजट के बारे में चर्चा की थी तो उस समय भी मैंने साफ कर दिया था कि चीन के प्रति हमारी नीति क्या है। इस लिये मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि इसका वे बिलकुल विचार न करें कि सरकार का एक मंत्री कोई बात स्पष्ट करता है, कोई दूसरा स्पष्ट नहीं करता है—चाहे कुछ रक्षा मंत्री बोलें, चाहे मैं बोलूं और चाहे प्रधान मन्त्री बोलें, वे सब सरकार की नीति का ही यहां पर वर्णन करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। हां, हम लोग अलग अलग जबान बोलते हैं, मुमकिन है उस में कोई ऐसा शब्द आ जाये जो पसन्द हो या न हो या थोड़ा सा इम्फैसिस में कुछ फर्क हो जाये लेकिन नीति एक ही होती है। सब एक ही नीति बोलते हैं जोकि सरकार की नीति है।

प्रधान मन्त्री तो इस सरकार की मुखिया हैं, नीति बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। उनकी बनाई हुई नीति है जिसको रक्षा मंत्री कहें या मैं कहूं।

माननीय सदस्य ने कृष्ण मेनन की बात कही। वे यहां पर नहीं हैं। उस वक्त वे हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश की नीति सरकार बनाती है। हमारी नीति किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं बनती है बल्कि देश के हित के आधार पर बनती है। माननीय सदस्य इस को भूल जायें कि श्री कृष्ण मेनन हमारे ऊपर दबाब डालते हैं। लेकिन अगर श्री कृष्ण मेनन कोई सही बात कहें तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिये सिर्फ इसलिये कि कृष्ण मेनन ने उसको कहा है। यह भी हमारी भावना नहीं होनी चाहिये। रंगा जी ने हमसे पूछा था......

SHRI RANGA : But it was because of that, he was sent out.

श्री दिनेश सिंह : अगर वे चले गये.... **(व्यवधान)**....मैं क्या और इस समय कह सकता हूं। यह जरूर है कि रंगा जी ने जो बात अभी कही कि हमको चीन से बातें करनी चाहिये, पाकिस्तान से बातें करनी चाहिये, यह तो हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट है कि जितनी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें हैं वह सबको मिल जुल कर शांतिपूर्ण ढंग से तय करनी चाहिये। यह तो हमारी एलान की हुई नीति है। हम मानते हैं कि इसी आधार पर इस संसार में शांति बनाई रखी जा सकती है। .... **(व्यवधान)**.....

SHRI RANGA: But they have never said till now that they are willing to talk to you. They have only been abusing you.

श्री दिनेश सिंह : मैंने तो नहीं कहा कि वे बात करने को तैयार हैं लेकिन क्या मैं कहूं कि हम भी बात करने को तैयार नहीं हैं।.... **(व्यवधान)**.....

SHRI RANGA : Where is the need for you to take the initiative ? Are you such a a statesman like person with so much of powers at your disposal as to tell him: "Come along, you are a little boy", etc. He is saying that he is going to kick you.

श्री दिनेश सिंह : मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें माननीय सदस्य, आचार्य जी को कठिनाई क्या हो गई। चीन जो बात कहता है क्या उसकी तरह से हम भी कहने लगें, भौंकनें लगें? मैं नहीं समझता हमारे देश का सम्मान उससे बढ़ता है। हमारे देश का सम्मान बढ़ता है सही बात को कायदे से, जाब्ते से और सही भाषा में कहने से। अगर वह गाली दें तो हम भी गाली देने लगें, मैं समझता हूं रंगा जी भी इसको पसन्द नहीं करेंगे। इस वक्त चाहे एक प्वाइन्ट बनाने के लिये वे कह दें लेकिन वे भी इसको पसन्द नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्टेट्समैन हैं या नहीं हैं, यह तो इतिहास लिखेगा कि स्टेट्समैन थे या नहीं। माननीय रंगा जी नहीं मानते हैं, वह बुजुर्ग हैं। मैं तो हमेशा उन को बुजुर्ग मानता हूं। बहरहाल, जो यहां पर सवाल है वह देश के हित का है। हमको जनता ने बैठाया है कि देश के हित की बात सोचें। चीन सोचे या न सोचे, हम को चीन के सोचने पर नहीं निर्भर रहना चाहिये। हमारे देश के लोग सोचते आये हैं, आज से नहीं, परम्परा है यहां की, और मुश्किल से मुश्किल बातों का हल निकालने की। अगर आज हम हल निकाल सकते हैं तो खुशी होनी चाहिये। किस लिये आचार्य जी कहते हैं कि हम को नहीं सोचना चाहिये। चीन के सोचने पर हम रुके रहें। हम को जरूर सोचना चाहिये और कोई हल निकाल सकते हैं तो निकालना चाहिये, क्योंकि देश में हम को बड़े बड़े काम करने हैं। इधर उधर की झंझटों से सुलझना है और देश के काम में लगना है।

तो मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की है। ....

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : यूनाइटड नेशन्स में मान्यता दिलाने के लिये जो प्रयास किया था वह जारी है या नहीं?

श्री दिनेश सिंह : सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की है जो कि कोई आश्वासन इस सदन में दिया गया हो उस के विपरीत हो। और सरकार की जो नीति है वह मैंने स्पष्ट कर दी ।

जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि चीन राष्ट्र मंडल में आये या न आये, यूनाइटेड नेशन्स में आये या न आये, तो उस के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारी क्या नीति रही है । इस आधे घण्टे के विवाद में उसकी चर्चा नहीं हुई थी, जो हम को तीन पॉइंट मिले थे उस में यह चीज नहीं थी, लेकिन उस के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से हम बातें करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात होगी कि ऐसे देश राष्ट्र मंडल में आयें जहां पर हम उन से बात कर सकें। लेकिन अगर वह राष्ट्र मण्डल के विचारों का उल्लंघन करते हैं तो हम को उनसे वहां पर निपटना है । आज हम अग्रसर नहीं हैं कि बात हो । लेकिन एक सही बात से हम को नहीं हटना चाहिये इस लिये कि चीन ने कोई गलत बात की हो ।

19.42 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, April 29, 1969/Vaisakha 9, 1891 (Saka).